an>

Title: Regarding monitoring centrally sponsored schemes and alleged corruption in the schemes in Bihar.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बिहार में केन्द्र द्वारा प्रायोजित पेयजल एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सभी योजनाओं में करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय हजारों करोड़ रुपये के कार्यक्रम प्रायोजित कर रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता राज्य का विषय होने के कारण इससे सम्बन्धित कार्यक्रमों को राज्य सरकार के द्वारा ही क्रियान्वित किया जा सकता है। विगत दो वर्षों में जो बुद्धिजीवी वर्ग है और गांव-देहातों के जो लोग हैं, वे सूचित करते हैं कि बिहार राज्य में पी.एच.ई.डी. विभाग केन्द्र से प्राप्त धन को ठीक ढंग से खर्च नहीं कर पा रहा है। जहां योजनाओं को पूरा धन केन्द्र देता है, उसमें भारी भ्रष्टाचार है और वहां पर लालफीतासाही व्याप्त है, इस कारण आम लोगों को केन्द्र के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के तीन जिले शिवहर, सीतामढ़ी और पूर्वी चम्पारण मे पी.एच.ई.डी. विभाग द्वारा जो चापाकल, पानी की टंकी या शौचालय बनाये गये हैं, उनमें भारी अनियमितताएं हैं। मैंने कुछ शौचालय और चापाकलों का स्वयं जाकर निरीक्षण किया तो पाया कि अधिकतर चापाकल और शौचालय बेकार पड़े हुए हैं और शौचालयों के चैम्बरों में भी सफाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत बन रही पानी की टंकी का भी पूरा प्रयोग नहीं हो पा रहा है। मैं यह जानना चाहती हूं कि वहां कहने के लिए तो प्रत्येक जिले में निगरानी करने के लिए एक जिला अनुश्रवण समन्वय व सतर्कता समिति गठित है, परन्तु बिहार सरकार के अधिकारियों के असहयोग के कारण पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धित कार्यक्रमों में निगरानी नहीं हो पा रही है। सांसद असहाय स्थिति में हैं।

मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार या सांसद एक विशेष टीम गठित करें और बिहार जैसे राज्यों में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में हो रही गड़बड़ी या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पहल करे। केन्द्र सरकार को भी राज्य सरकार से सहयोग लेकर केन्द्रीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ आम जनता को मिले, यह सुनिश्चित करना चाहिए। यह एक गम्भीर विषय है, जो आम लोगों से सीधे जुड़ा हुआ है, अतः इस पर तत्परता से कार्य करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।